संपादकीय जागरण

रविवार, 19 नवंबर, 2017 : मार्गशीर्ष शुक्ल 1 वि. 2074

विनम्रता से व्यक्तित्व की शोभा कई गुना बढ़ जाती है

# विवादों की फिल्म

**फिल्म पद्मावती** को लेकर उभरा विवाद जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है उससे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिलचस्पी इस विवाद को तूल देने में है। यह फिल्म तभी विवाद में आ गई थी जब राजस्थान में उसकी शूटिंग के समय निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई हुई थी। इस घटना के बाद संजय लीला भंसाली ने नाराज लोगों को यह आश्वासन दिया था कि फिल्म में कुछ भी प्रचलित मान्यताओं के विपरीत नहीं होगा, लेकिन जब फिल्म पद्मावती का ट्रेलर आया तो लोगों को यही लगा कि उन्हें दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। जिस तरह यह समझना कठिन है कि पद्मावती के मान-सम्मान को लेकर चिंतित लोग फिल्म की विषय वस्तु जाने और उसे देखे बिना इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि उनका चित्रण सही तरह नहीं किया गया है उसी तरह यह भी कि फिल्मकारों की ओर से इस काल्पनिक अंदेशे को दूर करने में तत्परता का परिचय क्यों नहीं दिया गया? क्या इसलिए कि हंगामा होता रहे और मुफ्त का प्रचार मिलता रहे? ऐसे सवाल इसलिए उभर आए हैं, क्योंकि फिल्म निर्माता सेंसर बोर्ड की हां या न का इंतजार किए और यहां तक कि उसे सही तरह फिल्म की प्रति सौंपे बगैर कुछ चुनिंदा लोगों को फिल्म दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें वे लोग शामिल नहीं होते जो सबसे ज्यादा आपत्ति प्रकट कर रहे होते हैं? आखिर सेंसर बोर्ड से पहले फिल्म को मीडिया के चुनिंदा लोगों को दिखाने और उनके जरिये जनता को संदेश देने का क्या मतलब? फिल्म निर्माता के रवैये पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति सर्वथा उचित है।

राजस्थान और साथ ही देश के अन्य हिस्सों के लोग फिल्म पद्मावती को लेकर एक ऐसे समय गुस्से में हैं जब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। निःसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ किसी को कला और रचनात्मकता के नाम पर धार्मिक, सांस्कृतिक प्रसंगों एवं मान्यताओं के निरादर की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। रानी पद्मावती के मामले में इस तरह के तर्कों का कोई मूल्य-महत्व नहीं कि इतिहास में तो ऐसा कोई पात्र मिलता ही नहीं। महत्व इस बात का है कि जन मानस में पद्मावती को लेकर धारणा क्या है? निःसंदेह मिथ्या धारणाओं को तोड़ने का काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय लोगों को जानबूझकर उद्वेलित-आक्रोशित करने का कोई मतलब नहीं। जैसे रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का अपना एक दायरा है वैसे ही विरोध और असहमति को प्रकट करने का भी। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि विरोध दर्ज कराने के नाम पर नाक काटने, सिर काटने जैसी धमकियां दी जा रही हैं। जो लोग भी शक्ति प्रदर्शन करने के साथ यह दर्शा रहे हैं कि वे मनमानी कर लेंगे वे न तो अपना भला कर रहे हैं और न ही समाज और देश की प्रतिष्ठा का। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई फिल्म प्रदर्शन के योग्य है या नहीं, इसे तय करने का अधिकार केवल सेंसर बोर्ड को है और यह काम उसे ही करने दिया जाना चाहिए।

# उचित कार्रवाई

**आचार संहिता** को दरकिनार कर विवाह के प्रीतिभोज के लिए अस्थायी बार लाइसेंस जारी करने पर लखनऊ के जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई को हर तरह से उचित ही कहा जाएगा। इस कार्रवाई से उन अधिकारियों को सख्त संदेश जाएगा जो अपने पद और कुर्सी को लेकर गुरूर में रहते हैं। उन ईमानदार अधिकारियों को बहुत ताकत और सुकून मिलेगा जो नियम-कायदों की चिंता करते हुए डटकर कर्तव्य पालन करते हैं।

प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते लागू आचार संहिता में स्पष्ट व्यवस्था है कि मतदान से 48 घंटे पहले से और मतगणना वाले दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन आबकारी अधिकारी ने एक दिसंबर को होने वाले इस समारोह के लिए सारे दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए लाइसेंस जारी कर दिया। ऐसा करते हुए शायद उन्होंने अपने को ही सर्वशक्तिमान समझा और मनमानी कर डाली। निर्वाचन आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर उनसे जवाब तलब किया जिसका वो समुचित जवाब नहीं दे सके। आयोग ने जिला आबकारी अधिकारी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनकी परिनिंदा की। इसे उनकी व्यक्तिगत फाइल में दर्ज करने के निर्देश हैं। साथ ही निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अन्य किसी भी मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग के सख्त तेवर देख संबंधित अधिकारी के पक्ष में कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वस्तुतः ऐसे अफसरों के बच निकलने पर वे अधिकारी मायूस हो जाते हैं जो नियम के पाबंद होते हैं। धीरे-धीरे वे भी इसी तरह का आचरण करने लगते हैं, लेकिन निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई अधिकारियों को न केवल नियमों का पालन करने को बाध्य करेगी बल्कि उन अधिकारियों का हौसला भी बढ़ायेगी जो नियम पालन करते हैं।

**इस कार्रवाई से उन अधिकारियों को सख्त संदेश जाएगा जो अपने पद और कुर्सी को लेकर गुरूर में रहते हैं**

## कह के रहेंगे

माधव जोशी

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया जा रहा सवाल राजनीति से प्रेरित है?**

**आज का सवाल**

क्या मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग बेहतर करना मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों पर मुहर है?

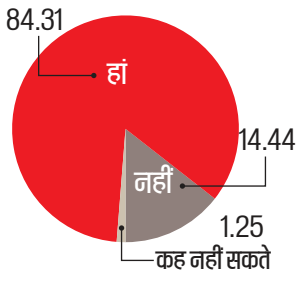


अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
**Y** -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# सुधारों के सिलसिले को समर्थन

संजय गुप्त

**मूडीज की रेटिंग पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि उसके नेतृत्व वाली सरकार के समय भारत की आर्थिक साख क्यों नहीं सुधर सकी?**

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताजा रपट भाजपा के साथ-साथ मोदी सरकार की शान बढ़ाने वाली है। 13 वर्ष बाद मूडीज ने भारत की आर्थिक सेहत में सुधार पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही यह नए सिरे से प्रमाणित हो गया कि मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे आर्थिक सुधार सही दिशा में भी हैं और फलदायी भी। यह रेटिंग एक ऐसे समय आई है जब अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमले कर रहे थे। हालांकि उनकी आलोचना राजनीतिक ही अधिक थी, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार कुछ दबाव का अनुभव कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली मई 2014 से ही अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कारोबार का बेहतर माहौल कायम करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक यह था कि काले धन के रूप में जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है उसे समाप्त किया जाए। यह काम नोटबंदी के फैसले ने बखूबी किया। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने पूरे देश में टैक्स की समान प्रणाली का दशकों पुराना सपना साकार किया। हालांकि जीएसटी के ढांचे में अभी भी कुछ खामियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें तत्परता के साथ दूर किया जा रहा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के साथ आधार ने भी आर्थिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आधार से न केवल अरबों रुपये की सब्सिडी की बर्बादी पर अंकुश लगा, बल्कि उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य भी पूरा हुआ।

नोटबंदी और जीएसटी को लेकर व्यापारियों के एक वर्ग में कुछ नाराजगी और साथ ही भ्रांतियां रही हैं, लेकिन अब जब इन दोनों फैसलों पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ भी अपनी मुहर लगा रहे हैं तो उनके संदेह भी दूर हो रहे हैं। आम तौर पर इन दोनों फैसलों का विरोध उन्हीं व्यापारियों ने किया जिन्हें दो नंबर का लेन-देन रास आ रहा था। वे हमेशा व्यवस्था में पारदर्शिता का विरोध करते रहे, लेकिन मोदी ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार ने नोटबंदी सरीखा कदम राजनीतिक जोखिम के बावजूद उठाया। उन्हें इस फैसले का राजनीतिक लाभ भी मिला। काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए उचित नहीं होती। एक तो इससे सरकार को टैक्स के रूप में जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता और दूसरे, जनकल्याण के कार्य भी प्रभावित होते हैं। जब काले धन पर अंकुश लगता है तो इसका सीधा लाभ सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। इससे वह गरीबों के कल्याण वाली योजनाएं चला सकती है और विकास के कहीं अधिक काम करा सकती है। जब समाज के सभी वर्गों का उत्थान होता है तभी देश समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। आखिर जब सभी इससे परिचित हैं कि समस्त आधारभूत ढांचा टैक्स के पैसों से ही खड़ा किया जाता है तब फिर टैक्स व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले उपायों के विरोध का क्या औचित्य?

अवधेश राजपूत

वर्तमान में किसी भी देश में निवेश की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियां यह चाहती हैं कि वहां अर्थव्यवस्था का संचालन पारदर्शी तरीके से हो। इसके प्रति आश्वस्त होने के बाद ही वे अपने कदम बढ़ाती हैं। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने बड़े और साहसिक आर्थिक सुधारों का बीड़ा उठाया। अब जब इन सुधारों पर एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाली रेटिंग एजेंसी ने अपनी मुहर लगा दी है तब उन सभी लोगों को दुष्प्रचार से बचना चाहिए जो देश की आर्थिक हालत पर आधारहीन तर्कों के सहारे राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे। यह गौर करने लायक है कि आर्थिक स्थिति की आलोचना विपक्षी दलों के साथ-साथ भाजपा के भी कुछ पूर्व नेता कर रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम यशवंत सिन्हा का है, जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्तमंत्री थे। यह संयोग ही है कि 2004 में वाजपेयी सरकार के समय ही मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। यशवंत सिन्हा को बताना चाहिए कि तब उन्होंने उसका स्वागत किया था या नहीं?

मूडीज की रेटिंग आने के बाद मोदी सरकार का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गुजरात विधानसभा चुनाव मोदी के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं। नोटबंदी और जीएसटी को मुददा बनाकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमले कर रही है। इस हमले की अगुआई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। वह शायद इसलिए मुखर और आक्रामक हैं, क्योंकि ऐसी दलीलें देना शुरू कर दी गई हैं कि जीएसटी के अमल में गड़बड़ियों के चलते भाजपा को गुजरात में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम तौर पर ऐसी दलीलें उन्हीं लोगों द्वारा दी जा रही हैं जो गुजरात की प्रकृति से परिचित नहीं हैं। गुजरात में चुनावी समीकरण एकदम अलग होते हैं। वहां गुजरात की अस्मिता का सवाल सबसे अधिक अहम होता है। इस मामले में भाजपा स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से आगे है। यह भी स्पष्ट है कि मूडीज की रेटिंग के कुछ त्वरित लाभ दिखने लगे हैं, जैसे रुपया मजबूत हुआ है। इसका असर गुजरात के चुनाव पर पड़ना चाहिए। वैसे भी भाजपा अपनी इस उपलब्धि को चुनाव में भुनाना चाहेगी।

तीन सालों से लगातार एक के बाद एक हार का सामना करने के साथ अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को गुजरात में अपनी रणनीति फिर से निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आर्थिक मोर्चे पर सरकार की तार्किक आलोचना करना मुश्किल हो गया है। फिलहाल कांग्रेस के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। वह अब तक राहुल गांधी के बारे में यह निर्णय नहीं कर सकी है कि उन्हें कांग्रेस की कमान कब सौंपनी है? कांग्रेस ने गुजरात में भाजपा को कड़ी टक्कर देने और इसी आधार पर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह फिर से बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन लगता है कि मूडीज की रेटिंग ने उसका खेल भी खराब कर दिया। इस रेटिंग पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को खुद इसका जवाब देना होगा कि उसके नेतृत्व में दस साल चली सरकार के समय भारत की आर्थिक साख क्यों नहीं सुधर सकी थी? कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि संप्रग के दस साल के शासनकाल में घपले-घोटालों के साथ-साथ जो नीतिगत निष्क्रियता आई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह इस निष्क्रियता का ही परिणाम रहा कि मूडीज समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रैंकिंग गिरा दी।

संप्रग के पूरे शासनकाल में भारत की रेटिंग में कोई सुधार नहीं हो सका तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि संप्रग सरकार से जिन आर्थिक सुधारों की अपेक्षा थी वे नहीं किए जा सके। मोदी ने सत्ता संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं में आर्थिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। यह सही है कि मूडीज ने 2015 में मोदी सरकार की रीति-नीति से असहमति जाहिर की थी, लेकिन आखिरकार वह भारत की प्रगति को स्वीकार करने के लिए विवश हुई। इसका श्रेय मोदी सरकार की सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को ही जाता है।

response@jagran.com

# हवा हो रही हवा-हवाई

हास्य-व्यंग्य

निर्मल गुप्त

**अगर अब जिंदा रहना है तो सांस रोककर दिल थाम लो। चुप रहो। चुपचाप जियो या फिर मर जाओ**

हवा दिल्ली की है, पर चिंतित पूरा मुल्क है। लगता है कि ऐसी कोई नई कहावत बनने वाली है कि जब राजधानी छींकती है तो पूरा देश खुद-ब-खुद नाक पोंछने लगता है। लोगों के पास परेशान होने के लिए अन्य कारक और प्रसंग मौजूद हैं, फिर भी बताने वालों ने बता दिया है कि मामला इतना संगीन हो चला है कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में मुंह पर मास्क बांध लेने के बावजूद यदि किसी ने उसे बिचकाने की जुर्रत भी की तो नतीजे सनसनीखेज हो सकते हैं। ऐसे में अवाम पसोपेश में है कि मुंह को बिना टेढ़ा-तिरछा किए सेल्फी खींचनी ही पड़े तो कैसे खींची जाए? फिर चेहरे पर मास्क किसी भी चांद से मुखड़े पर चंद्रग्रहण की तरह मालूम होता है और यह बात सब जानते हैं कि संप्रति बिन सेल्फी जीवन कुछ ऐसा हो चला है जैसे मसूरी के बिना वृथा देहरादून। या जैसे बिन नागिन नृत्य के ब्याह बारात का गाना बजाना। जैसे नौटंकी में किसी कालजयी गीत का श्रवण करते हुए राइफल का ट्रिगर फंस जाने की वजह से हवा में गोली दागने के सुख से वंचित रह जाना। जैसे तमाम कुचेष्टाओं के बावजूद पुलिस द्वारा बाहुबली जी के खिलाफ दफा 307 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि के चलते बदचलनी की किसी धारा में मुकदमे का दर्ज हो जाना।

प्रदूषण से निबटने के लिए ऑड और इवन का पिछला फार्मूला यूटर्न लेकर वापस विलंबित सुझाव के लालफीते वाले ठंडे बस्ते में पहुंच गया है। जिस तरह हर कोई दूसरे के सुझाए उपायों को खारिज कर रहा है उससे यही लगता है कि सबका साझा मकसद न खुद कुछ करना है और न दूसरों को कुछ करने देना है। शायद न तुम करो- न हम करें का कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन के साथ यह भी दिखाया जा रहा है कि चिंता न करो, हम कुछ कर रहे हैं। कोई कुछ करने के लिए आगे बढ़ता दिखता है या ऐसा करने का दिखावा करता है तो यह शोर मच जाता है कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे माहौल में आम आदमी के पास अब ले-देकर शायद सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं। एकाध ऑप्शन और भी हो, कौन जाने?

वैसे तो तमाम विकल्प खुले हैं फिर भी सहज उपलब्ध तरीके यही दिख रहे हैं: एक तो यह कि जो होगा, देखा जाएगा कहकर कंधे उचका लिए जाएं या जल्द से जल्द घर में मासिक आसान किस्तों पर ब्रांडेड प्यूरीफायर इंस्टॉल करवा लिया जाए और फिर कर्ज की किस्त अदा करते हुए घर के भीतर के घटते प्रदूषण स्तर का मजा लिया जाए। साथ ही साथ प्यूरीफायर लगवा पाने में असफल पड़ोसी के बच्चों को हरदम खांसते, छींकते देखकर अपार आनंद का अनुभव किया जाए। सयाने कह गये हैं कि निजी सुख के बिरवे प्रायः पराये दुःख की क्यारी में ही पनपते पाये जाते हैं।

प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली की हवा खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है। यदि यमुना का जल स्तर इस तरह की गति को प्राप्त हुआ होता तो अब तक ऊंचाई पर टंगे लोग या तो हाय-हाय कर रहे होते या जलप्लावित लोगों के लिए नमक-अजवाइन की पूड़ी और जीरे वाले आलू की सब्जी के पैक बनवा और बंटवाकर समाज सेवा में अपनी भागीदारी का लुत्फ उठा रहे होते। लेकिन यह पानी का नहीं हवा का मामला है। हवा जब दूषित होती है तो किसी पर रहम नहीं करती। ऊंची-नीची, छोटी-बड़ी हर तरह की नाक के नथुनों तक जा धमकती है। एक समय था जब बुरे दिन आते थे तो हवा और पानी के सहारे लोग वक्त काट ले जाते थे। वक्त की यह काटा-पीटी तब तक चली जब तक जल हथेली की ओक से पी लिया जाता था। फिर पानी बोतलबंद हुआ तो गुरबत में घिरे आदमी के लिए हवा का सहारा ही रह गया। अब यह बचीखुची आस भी गई। अब जिंदा रहना है तो सांस रोककर दिल थाम लो। चुप रहो। चुपचाप जियो या फिर मर जाओ। सवा अरब की आबादी में बीस-तीस, पचास-साठ हजार मर भी जाएं तो उससे जनसंख्या के आंकड़ों पर क्या अंतर पड़ना है। कहा भी जा रहा है, क्यों परेशान हो? भोपाल गैस जैसी त्रासदी थोड़ी आ गई है।

हवा हवाई हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब हॉलैंड के फूलों वाली महक भरी हवा से लेकर डेनमार्क की डेयरी प्रोडक्ट वाली पौष्टिक हवा और देसी शराब के ठेके से उठने वाले मादक भभकारे से लेकर स्वदेशी भावुक रसभीनी बयार तक टेट्रापैक में भर कर बिकने के लिए ऑन और ऑफलाइन उपलब्ध हो जाएगी। इसे वक्त और जरूरत के मुताबिक इष्ट मित्रों को बतौर गिफ्ट भेजने की सुविधा तो रहेगी ही। मुल्कों के बीच जब हवा का खुलकर आयात-निर्यात होगा तो वैश्विक सौहार्द के नए रोशनदान खुलेंगे। दिल्ली की चांदनी चौक वाली हवा जब लाहौर के अनारकली बाजार में वितरित होगी तो देखते ही देखते दो कौमी नजरिये पर बनने वाले मुल्क की अवधारणा के चकनाचूर होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। डिब्बाबंद हवा वैसे भी खांटी सेक्युलर होगी। गनीमत है कि हवा का रंग किसी ने देखा नहीं, नहीं तो हवा को भी किसी न किसी धार्मिक रंग से जोड़ दिया जाता। बहरहाल अब पहले जैसी हवा नहीं रहने वाली। गुपचुप चलने वाली दिल्ली की हवा की तो बात ही कुछ और हो ली है। हवा से उठे सवाल बड़े जोरशोर से उठने हैं। असल हवा तो बाजार की आनी है।

response@jagran.com

## ऊर्जा

### मित्रता

पारंपरिक रिश्तों के कमजोर हो जाने से अब संबंधों का दारोमदार मुख्यतया मित्रों पर है, इसलिए उनका सुविचारित चयन आवश्यक है। खून के रिश्तों से अधिक पुख्ता वे हैं, जो वक्त पर हाथ थाम लें। संपन्नता के दौर में मित्र मंडराने लगते हैं। खरे मित्र की परख विपत्ति या कठिन दौर में होती है। जब आप सारी दुनिया को कुशल-दुरुस्त होने का स्वांग करते हैं, तब वह आपके दर्द को भांप जाता है। उसका आगमन कदापि बोझ नहीं होता, उसका घर कभी सुदूर नहीं होता। मित्रता का अर्थ यह नहीं कि मतभेद नहीं होंगे। विद्वान प्लूटार्क ने कहा था, मुझे वह दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी मुंडी हिलने पर अपनी मुंडी हिला दे, ऐसा मेरी परछाई बेहतर कर लेती है। सही मित्र हमारी रग-रग समझता है, उससे अपनी चिंताएं जताई नहीं जातीं। हमारे लिए जो उचित है, उसमें वह सहभागी बनता है। वह झकझोरता है कि तफरीह के लिए नहीं, बीमार मां के पास जाना है, वह बताता है कि शर्ट का बटन टूटा है या जूते का फीता खुला है। सच्चा दोस्त वह नहीं, जो लग्जरी गाड़ी या बेशकीमती फोन खरीदने के लिए उकसाए या कर्ज दे बल्कि इनके लिए मदद देते हाथ पकड़ ले। मित्रता की अथाह शक्ति का आधार ढाई अक्षर का शब्द प्रेम है, जो वह सब करा सकता है, जो किसी पावर के बूते की बात नहीं। इसी शक्ति के दोहन के उद्देश्य से पेशेवर, कारोबारी, सरकारें एक दूसरे का हाथ थामती हैं।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था कि दोस्ती ही एकमात्र सीमेंट है, जो दुनिया को एकजुट रख सकती है। अंदरूनी सरोकार दूसरों से साझा न करने से लोगों को अकेलापन खाए जा रहा है। डिप्रेशन, उद्विग्नता, सिजोफ्रेनिया जैसे मनोरोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार रॉबर्ट ब्रॉल्ट कहते हैं, 'मानसिक रोगियों को मनोचिकित्सक की कम, मित्र की ज्यादा जरूरत रहती है।' ईमानदार मित्र सबसे नायाब उपहार है। जिन्हें शिकायत है, आजकल खरे मित्र नहीं मिलते, उन्हें भीतर झांकना होगा कि चूक कहां है। आर.डब्ल्यू. इमर्सन की सलाह है, 'पहले स्वयं किसी के अच्छे मित्र बन जाएं'। आज के मुखौटा प्रिय समाज में मित्रों की पहचान में सूझबूझ अपनानी होगी। एक गुलाब आपकी जिंदगी को महका सकता है, सोच ऐसी हो: विनम्रता सभी से, घनिष्ठता कुछ से और पूर्ण विश्वास दो-तीन पर। तभी जिंदगी खुशनुमां रहेगी।

हरीश बड़थ्वाल

## तथ्य-कथ्य | भारतीयों की नजर में भारत की बड़ी समस्याएं

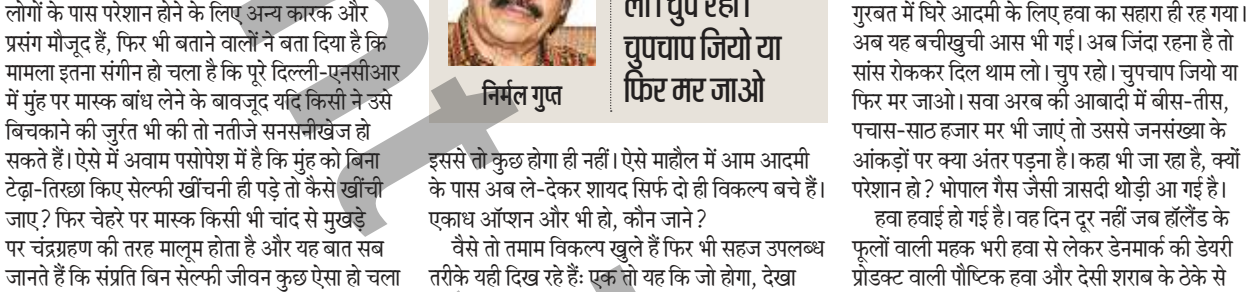


## राहुल की ट्वीट 'खानगी'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के नए तेवर और कलेवर को लेकर सियासी गलियारों में हलचल का दौर जारी है। कांग्रेस में ही नहीं पार्टी के बाहर विरोधी राजनीतिक खेमे में भी राहुल के कभी चुटीले, कभी तीखे तो कभी शायरी, गीत या कविता के जरिये सियासी निशाना साधने की नई शैली को खास तौर पर नोटिस किया जा रहा है। खासकर उनके हास्य-व्यंग्य और गीत- शायरी वाले मारक ट्वीट के सियासी असर को लेकर पार्टी में उत्साह का आलम है। पार्टी नेता यहां तक दावा कर रहे कि जीएसटी की दरें घटाने का फैसला तो राहुल के गब्बर सिंह टैक्स वाले बयान की वजह से हुआ। इसी तरह दिल्ली में गंभीर प्रदूषण और धुंध पर 'सीने में जलन, आंखों में तूफां सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है?' ट्वीट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। महंगाई पर सीधे सियासी वार के लिए 'महंगी गैस, महंगा राशन, बंद करो खोखला भाषण, दाम बांधों, काम दो वरना खाली करो सिंहासन' जैसे ट्वीट सोशल मीडिया में काफी छाए रहे। वैसे राहुल ने सोशल मीडिया में उनकी प्रभावशाली मौजूदगी पर हाल ही में कहा भी कि तीन-चार लोगों की टीम उनके ट्वीट में भूमिका निभाती है। राजनीतिक विषयों पर वह खुद भी ट्वीट करते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे राहुल का सोशल मीडिया का यह प्रभाव पार्टी को कितना फायदा दिलाएगा इसका पता तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के नतीजों से ही चलेगा।

## राजरंग

### बड़े सपने के फायदे

कुछ समय पहले तक शंकाएं जाहिर करने वाली तमाम राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इन दिनों मोदी सरकार के गुण गा रही हैं। साल भर पहले जब सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने रोजाना 40 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा था तो रेटिंग एजेंसियों ने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। खुद गडकरी से जब इस विषय में सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि बड़े लक्ष्य अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए रखे जाते हैं। जब 40 किलोमीटर का लक्ष्य रखेंगे तो 30 किलोमीटर तो पा ही लेंगे। अब उनकी बात सही साबित होने लगी है। हाल में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपने नवीनतम आकलन में इस तथ्य की पुष्टि की है कि अब देश में रोजाना 23 किलोमीटर सड़कें बनने लगी हैं और जिस तरह सरकार तथा एनएचएआइ काम कर रहे हैं उससे वह दिन दूर नहीं जब रोजाना 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने देखने से ही उनके साकार होने की नींव पड़ती है। इसी क्रिसिल ने दो वर्ष पहले कहा था कि सरकार भले ही रोजाना 15 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा कर रही हो, मगर वास्तव में केवल नौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो पा रहा है।

### वर्मा बनाम वर्मा

सत्ता के गलियारों में वर्मा बनाम वर्मा की चर्चा जोरों पर है। दोनों वर्मा एक ही अधिकारी हैं। वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी आलोक वर्मा। जो अभी सीबीआइ के निदेशक हैं। इसके पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। कमिश्नर रहते हुए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दी थी, सीबीआइ निदेशक के रूप में उसके ठीक उल्टा रिपोर्ट दे रहे हैं। मामला जेएनयू के छात्र नजीब की गुमशुदगी का है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक ऑटो ड्राइवर ढूंढ निकालने का दावा किया था, जिसने नजीब को जामिया में छोड़ा था, लेकिन अब सीबीआइ ने हाईकोर्ट को बताया है कि दिल्ली पुलिस की मार की वजह ऑटो ड्राइवर ने यह बात कबूल थी, जो कि सिरे झूठ है। कहना मुश्किल है दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा सही बोल रहे थे या कि अब सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा सही बोल रहे हैं। अक्सर पुलिस और सीबीआइ के दावों में अंतर होता है यह तो सुना था लेकिन दोनों ही महकमों में एक शख्स के अलग-अलग रूप अब देख भी लिए हैं।

## ट्वीट-ट्वीट

इंदिरा गांधी जैसा बनने का ख्वाब तो सब देखते है, पर इंदिरा जैसा बनना मुश्किल ही नहीं असंभव है! आशा है माननीय रक्षा मंत्री भी अब तक यह बात समझ चुकी होंगी।

साध्वी खोसला@sadhavi

हैरानी की बात है कि सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिले बिना ही पद्मावती के निर्माताओं ने कुछ संपादकों को यह फिल्म दिखा दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि पद्मावती काल्पनिक है या इतिहास पर आधारित। चलिए अब इन संपादकों को ही सेंसर बोर्ड का सदस्य बना देना चाहिए।

सुधीर चौधरी@sudhirchaudhary

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जौहरकुंड में तीन बार राजस्थान की वीरबालाओं ने जौहर कर प्राणोत्सर्ग कर, अपनी मर्यादा की रक्षा की! तीन बार चित्तौड़गढ़ में आक्रमण हुआ, पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बहादुर शाह और तीसरा मुगल बादशाह अकबर के समय।

मालिनी अवस्थी @maliniawasthi

कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था पर आई किसी नकारात्मक खबर का तो खूब महिमामंडन करते हैं, लेकिन सकारात्मक खबर पर कहीं गायब हो जाते हैं। हद दर्जे का पाखंड। असल में ये लोग हमेशा आधा गिलास खाली देखना चाहते हैं।

राहुल कंवल@rahulkanwal

## जनपथ

'ऑटोरिक्शा' से करें शरद मियां संतोष,
जब पंगा खुद ही लिया भला किसे दें दोष।
भला किसे दें दोष होश बेवजह गंवाया,
हाथ न आए राम और ना पाई माया।
लिए कटोरा हाथ सीट की मांगो भिक्षा,
कांग्रेस के साथ चलाओ 'ऑटोरिक्शा'।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शु